(गोरख पांडेय की कविता)

सोचो तो

बिलकुल मामूली चीज़ें हैं
आग़ और पानी
मगर सोचो तो कितना अजीब होता है
होना
आग़ और पानी का
जो विरोधी हैं
मगर मिलकर पहियों को गति देते हैं
वैसे, सोचो तो अंधेरे में चमकते ये हज़ारों हाथ हैं
इतिहास के पहियों को
रोटी–रचना और मुक्ति के पड़ावों की ओर बढ़ाते हुए
इतिहास की किताबों में इनका ज़िक्र भी न होना
सोचो तो कितना अजीब है

सोचो तो मामूली तौर पर
जो अनाज उगाते हैं
उन्हें दो जून अन्न ज़रूर मिलना चाहिए
उनके पास कपड़े ज़रूर होने चाहिए
जो उन्हें बुनते हैं
और उन्हें प्यार मिलना ही चाहिए
जो प्यार करते हैं
मगर सोचो तो यह भी कितना अजीब है
कि उगाने वाले भूखे रहते हैं
और अनाज पचा जाते हैं
चूहे और बिस्तरों पर पड़े रहने वाले लोग
बुनकर फटे चीथड़ों में रहते हैं
और अच्छे–से–अच्छे कपड़े
प्लास्टिक की मूर्तियां पहने होती हैं
ग़रीबी में प्यार भी नफ़रत करता है
और पैसा नफ़रत को भी प्यार में बदल देता है
सोचो इस तरह कितनी अजीब और
कभी–कभी एकदम उलटी होती हैं चीजें
जिन्हें हम मामूली समझकर चलते हैं

वैसे, सोचो तो सोचने को बहुत कुछ है
मगर सोचो तो यह भी कितना अजब है
कि हम सोच सकते हैं
मसलन हम सोच सकते हैं
कि फ़सल ज़मींदारों के बिना भी उग सकती है
जैसे परमाणु अस्त्रो के बिना भी कायम हो सकती है शांति
जो कल–कारखाने अपने हाथों चलाते हैं
वे उनके मालिक भी हो सकते हैं
पानी जोंकों के बिना भी बहता रह सकता है
और आग़ झोंपड़े जलाने के लिए नहीं
बल्कि ठंड से कांपते लोगों को
बचाने के काम आ सकती है

सोचो तो सिर्फ़ सोचने से
कुछ होने–जाने का नहीं
जबकि करने को पड़े हैं
उलटी चीज़ों को उलट देने जैसे ज़रूरी
और ढेर सारे काम
वैसे, बिना सोचो तो यह भी कितना अजीब है
कि बिना सोचे कुछ होने–जाने का नहीं
जबकि
होते हो
इसलिए सोचते हो।

पेज 1 का शेष भाग

15 अगस्त पर नागरिकों द्वारा सम्मानों की घोषणा

इन सभी पर सरकारों की कोपदृष्टि होने के बावजूद, निरंकुश राजशाही के आदी राजनेता नंगे हुए हैं। हरियाणा काडर के आईएएस अधिकारी खेमका ने मुख्यमंत्री हुड्डा, उनके वरिष्ठ नौकरशाहों, डी एल एफ एवं सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वड्रा की साक्षात आपराधिक साजिश का भांडा फोड़ किया। इस साजिश के तहत वड्रा ने डीएलएफ से 'उधार' लेकर गुड़गांव में डीएलएफ की ही ज़मीन खरीदी। इस ज़मीन के लैंडयूज़ को हुड्डा एवं उनके नौकरशाहों ने खरीद के उपरोक्त सौदे के तुरंत बाद बदल दिया। इससे उस ज़मीन के दाम सैंकड़ों गुणा बढ गये। अब वड्रा ने वही ज़मीन वापस डीएलएफ को बेच दी और तकरीबन 200 करोड़ से ऊपर 'सफ़ेद' कमाई कर ली। खेमका ने इस अंधेरगर्दी को नंगा करते हुए अपनी सौ पृष्ठों की रिपोर्ट में सारी आपराधिक साजिश को तार-तार कर दिया।

दुर्गा शक्ति की तो अभी जुम्मा-जुम्मा चार साल नौकरी भी पूरी नहीं हुई है। उत्तर प्रदेश काडर की यह आईएएस अधिकारी समाजवादी पार्टी सरकार के खनन माफ़ियाओं का शिकार बनी, जब उन्होंने बतौर एस.डी.एम गौतम बुद्ध नगर सदर रेत-तस्करों पर प्रशासनिक शिकंजा कसा। इस तरह वह सीधे-सीधे मुलायम -अखिलेश-शिवपाल-आजम-रामगोपाल की सामंती लूट के निर्बाध रास्ते का रोड़ा बन गयी। दुर्गा की बहादुरी एवं कर्त्तव्य-निष्ठा ने समस्त देश के प्रशासनिक अधिकारियों में प्रेरणा का संचार किया है। राजनैतिक दलों को भी, शर्मा-शर्मी में ही सही, खनन तस्करी के मामले से दो-चार होना पड़ रहा है।

गुजरात काडर के आईपीएस अधिकारी सतीश वर्मा और वहीं के न्यायिक मजिस्ट्रेट एस.पी. तमंग ने राज्य के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के हत्याचार का पर्दाफ़ाश करने में प्रमुख भूमिका निभाई है। मोदी की निरंकुश तानाशाही ने तमाम वरिष्ठ अधिकारियों को चुप कराने में सफ़लता पाई। यहां तक कि उच्चतम न्यायालय द्वारा वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी राघवन की अध्यक्षता में बनाई गयी एस आई टी को भी कार्पोरेट दुनिया के दबाव से मोदी ने अपने पक्ष में कर लिया था। मोदी को बरी करने वाली राघवन की रिपोर्ट एक हास्यास्पद दस्तावेज़ ही है। पर सतीश वर्मा ने लगातार अपनी रिपोर्टों एवं शपथपत्रों द्वारा गुजरात नरसंहार एवं वहां की फ़र्जी पुलिस मुठभेड़ों में मोदी की भूमिका को रेखांकित किया है। इसी तरह मैजिस्ट्रेट एस पी तमंग ने इशरत जहां पुलिस मुठभेड़ मामले को अपनी छान-बीन में फ़र्जी करार दिया। जाहिर है जब स्वयं मोदी, उसका गृहमन्त्री अमितशाह, उसके चहेते पुलिस अधिकारी बनजारा का सशस्त्र गिरोह, इस मामले (फ़र्जी मुठभेड़ में चार व्यक्तियों को दसियों दिन पुलिस हिरासत में रख कर मार दिया गया था) में पूरी तरह शामिल हों तो एक मैजिस्ट्रेट का सच्चाई पर अडिग रहना कितना जोखिम भरा काम है। इस युवा मैजिस्ट्रेट की दिलेरी एवं न्यायप्रियता देश की तमाम न्यायपालिका के लिये जीती जागती मिसाल है। हरियाणा में खाप पंचायतों की स्त्री-विरोधी मानसिकता किसी से छिपी नहीं है। साथ ही, आये दिन वहां के गांवों में कमज़ोर तबकों की लड़कियों का यौन-उत्पीड़न भी आम बात है। ऐसे में राज्य की दो महिला जजों ने दोषियों को दो अलग-अलग मामलों में फ़ांसी की सज़ा देकर लैंगिक न्याय की नयी मिसाल कायम की। न्यायाधीष वाणी गोपाल शर्मा की तैनाती करनाल में बतौर अतिरिक्त सैशन जज थी। उनके सामने खाप पंचायत के उकसाने पर दोनों परिवारों द्वारा इज्ज़त के नाम पर गांव के एक युवा जोड़े की हत्या का मामला आया। इस कुख्यात प्रसंग में पंचायत का एक सदस्य सार्वजनिक रूप से बढ-चढ कर हत्या को उचित ठहरा रहा था। न्यायाधीश शर्मा ने न केवल हत्यारों को फ़ांसी की सज़ा सुनाई बल्कि उस पंच को भी आजीवन कारावास का दंड दिया। इस अकेली सज़ा ने खाप पंचायतों की मनमानी पर अंकुश लगाने का काम किया। एक और न्यायधीश सरिता गुप्ता ने भी ऐसा ही साहसपूर्ण फ़ैसला भिवानी के एक 'इज्जत' मामले में दिया। भिवानी के एक गांव में एक बलात्कार का सज़ायाफ्ता, जो जेल से पैरोल पर आया हुआ था, ने अपने एक साथी की मदद से दो विधवाओं की सरेआम दिनदहाड़े हत्या कर दी। ये दोनों विधवायें इस बलात्कारी की रिश्तेदार थीं और बलात्कारी को चिढ इस बात की थी कि उनका 'चरित्र' ठीक नहीं है। लिहाज़ा दोनों हत्यारों ने दोनों महिलाओं को लाठियों से पीट-पीट कर मार डाला। यह नृशंस कुकृत्य सारे गांव के सामने हुआ था। पर जिन्हें चश्मदीद गवाह बनाया गया वे दोषियों से मिल गये और अदालत में मुकर गये। फ़िर भी न्यायाधीश सरिता गुप्ता ने परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर दोनों अभियुक्तों को फ़ांसी की सज़ा दी।

'मज़दूर मोर्चा' परिवार उपरोक्त सभी सम्मानित व्यक्तियों को समाज का असली हीरो मानते हुए उन्हें जनता की ओर से बधाई देता है। भारतीय समाज को उनके योगदान पर गर्व है।

शासकों का जश्न-ए-आज़ादी, आम जनता की बरबादी

आम आदमी इसे अपना त्योहार मान भी कैसे सकता है? उसे मिला ही क्या है? उसके हिस्से तो आई है केवल भूख, बेरोज़गारी, बिमारी व जहालत। आज़ादी के नाम पर केवल उसकी गुलामी का स्वरूप बदला है। आज़ादी तो केवल उस राजनीतिक गिरोह को मिली है जो सत्ता के बलबूते पूरे देश को लूटने व आम जनता को प्रताड़ित करने में जुटा है। इसी से प्रफुल्लित यह गिरोह इस जश्न के द्वारा अपनी खुशी एवं सत्ता के दम्भ का प्रदर्शन करता है।

एस डी एम दुर्गा शक्ति नागपाल का निलम्बन

ऐसा तभी संभव है जब यादव बाहुबलियों को बेखौफ़ लूट की छूट मिली रहे और मुस्लिम मतदाताओं की मुलायम सिंह को अपनी सुरक्षा का पहरेदार मानने की भावना कायम रहे। बेशक यह एक बदनाम होने वाली जिद नज़र आ रही हो पर दुर्गा के निलम्बन पर अड़े रह कर मुलायम सिंह ने अपनी वोट-बैंक नीयत में कमी नहीं होने दी है।

दरअसल मुस्लिम मतदाताओं का ध्रुवीकरण, मोदी के डर से, कांग्रेस के पक्ष में होता जा रहा है। वे जानते हैं कि मुलायम की पार्टी को लोकसभा चुनावों में मत देना हर तरह से भाजपा और नरेन्द्र मोदी के फ़ायदे में जायेगा। अखिल भारतीय स्तर पर कांग्रेस ही भाजपा और मोदी की काट बन सकती है। लिहाजा, मुलायम को आज ऐसे मुद्दे खड़े करने का फ़ायदा है जिनसे वे मुसलमानों के सबसे बड़े पैरोकार नज़र आयें।

दुर्गा नागपाल के द्वारा गांव में अतिक्रमण हटाने की मुहिम के अन्तर्गत एक निर्माणाधीन मस्जिद की अनधिकृत दीवार गिराने के निर्देश से मुलायम को वांछित तरीके से मुद्दा खड़ा करने का बहाना मिल गया। इसी लिये तब से अखिलेश यादव मुस्लिम भावनाओं को आहत करने का आरोप दुर्गा के सिर मढते आ रहे हैं।

मुलायम यह भी जानते हैं कि अपने बाहुबलियों की दबंगई के बिना उनके ग्रामीण वोट भी, कुशासन एवं भ्रष्टाचार के चलते छिटक जायेंगे। ऐसे में इन बाहुबलियों को आश्वस्त रखना भी जरूरी है। दुर्गा नागपाल का निलम्बन उनकी यह जरूरत भी पूरी करता है। इस निलम्बन से सारे प्रदेश की नौकरशाही को यह संदेश मिल गया है कि समाजवादी पार्टी के करीबी बाहुबलियों की लूट में दखलंदाजी करना महंगी पड़ेगी।

परवाड़े के कार्टून

काश कि इन्होंने भी मिड-डे मील खाया होता तो यक़ीनन, इस देश का उद्धार हो जाता

सुधी पाठकों से हमारा अनुरोध

'मज़दूर मोर्चा' को पढने वाले सुधी पाठक भली-भांति समझते हैं कि यह एक पूर्णतया ग़ैरव्यवसायिक प्रयास है। आज की इस महंगाई के ज़माने में इसे नियमित निकालने की कठिनाइयों का अनुमान लगाना भी सुधी पाठकों के लिये कठिन नहीं होगा। इन कठिन परिस्थितियों में 'मज़दूर मोर्चा' को नियमित बनाये रखने के अलावा इसकी गुणवत्ता को और बढाने के लिये अनुरोध है कि डाक से प्राप्त करने वाले पाठक वार्षिक 100/- रुपया अथवा आजीवन 1000/- रुपया की सहयोग राशि 'मज़दूर मोर्चा' को भेजने की व्यवस्था करें। सहयोग राशि 'मज़दूर मोर्चा' कार्यालय 1डी/2 बी पी (हार्डवेयर चौक) एनआईटी फ़रीदाबाद के पते पर बजरिया मनीआर्डर अथवा चेक भेजी जा सकती है। इसके अलावा यूनियन बैंक ऑफ़ इन्डिया की किसी भी शहर की किसी भी ब्रांच में मज़दूर मोर्चा के खाता संख्या 4150 में सीधे भी रकम डाली जा सकती है।

ज़िला फ़रीदाबाद व पलवल के पाठक अपने हॉकर से प्राप्त कर सकते हैं। पाठकों से यह भी अनुरोध है कि 'मज़दूर मोर्चा' पढने के बाद अपनी टिप्पणियां, आपत्तियां, सुझाव इत्यादि साधारण डाक, ई मेल अथवा 9999595632 पर एसएमएस के द्वारा अवश्य भेजें। यह लेखन एवं सामग्री चयन में काफ़ी उपयोगी सिद्ध होगा।

-संपादक मंडल